DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **Hindustan Times** DATE NEW DELHI SATURDAY MAY 24, 2025

DDA to upgrade Dwarka footpaths

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) will redesign footpaths along arterial roads in Dwarka to meet Indian Roads Congress (IRC) standards, officials said. The project includes raising footpaths to uniform height, improving surfaces, ensuring proper drainage, and enhancing pedestrian walkability. Completion is expected within six to seven months.

DDA begins cleaning Kitchener lake

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) has begun cleaning and maintaining the 66-acre Kitchener Lake near Dhaula Kuan, officials familiar with the matter said.

The DDA is in the process of appointing an agency for the year-long project, with an allocated budget of ₹25.09 lakh. The effort will involve both manual and mechanised cleaning of the lake and its catchment area.

"The lake has immense ecological value but has long suffered from neglect and urban runoff," an official said. "Most of the area has already been cleaned and desilted, and the remaining work will now be completed."

The clean-up follows a notice issued by the National Green Tribunal (NGT) in November 2024, in response to a petition filed by a local resident seeking the lake's revival. Since then, the DDA has submitted several reports to the tribunal detailing its efforts.

Clear water a far cry in the lakes of Delhi

May 15, 2025: HT reported how lake revival projects are failing.

Earlier this week, the DDA informed the NGT that its corrective measures had already improved water quality in the lake. Plans are also being explored to connect the water body to a sewage treatment plant (STP) as a more permanent, long-term solution.

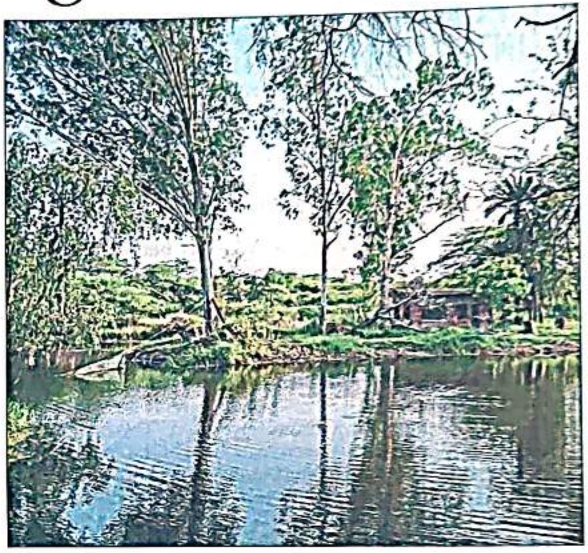

The 66-acre Kitchener Lake near Dhaula Kuan and its catchment area will be cleaned at a cost of ₹25.09 lakh. VIPIN KUMAR/HT

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, MAY 24, 2025

DDA to use treated water for parks

Vibha Sharma
@timesofindia.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) has decided to take the help of an expert agency to implement a water management system for the irrigation of its parks and green areas for the long term.

The authority recently invited a consultancy proposal to help design a city-wide management and feasible network design for supplying recycled water to around 750 parks across Delhi. The selected consultant will be awarded prize money and the opportunity to develop a detailed project report along with the final tender documents.

"Recognising the importance of efficient irrigation systems, DDA aims to address the water requirements at parks by leveraging treated water sources. The project includes either utilising water

The authority said that the initiative aims to revamp the current water distribution system, which now relies on groundwater and water tankers

from nearby Sewage Treatment Plants (STPs) or installing new STPs to meet irrigation needs, tapping raw sewage, analysing the efficacy of the existing irrigation system, and suggesting improvements or modifications, etc. in a cost-effective and environmentally sustainable manner," the authority said in its expression of interest. The deadline for submitting the concept notes and proposals is May 28.

According to DDA, the selected consultant should complete the design and planning in four months. The scope of work would also include mapping water demand in different regions, identifying nearby sources of treated wastewater such as STPs, and evaluating the potential of tapping raw sewage where needed to build new treatment capacity. The initiative will be rolled out across all ten horticulture divisions of the DDA. Officials confirmed that each zone has been assigned to develop strategies for making parks self-sufficient regarding water.

DDA manages over 16,000 acres of green spaces in Delhi. This encompasses 10,400 acres comprising 729 public parks, 21,000 acres of biodiversity parks, and 3,500 acres of Yamuna floodplain undergoing various stages of restoration.

The authority said that the initiative aims to revamp the current water distribution system, which now relies on groundwater and water tankers mostly, both of which fall short during peak summer. "Delhi faces substantial sewage issues, and treating this water for irrigation would benefit both environmental conservation and financial resources," the authority said.

According to expression of interest issued by DDA, the selected consultant will gather and review all relevant historical and current data on parks, including information on existing irrigation methods, water demand, treated water supply, and potential sewage collection points. "Data will be compiled from relevant agencies, previous studies, and available records. Accordingly, a detailed profile of each park will be created, highlighting existing infrastructure and limitations. Thereafter, a physical site inspection of all parks will be conducted. A photographic and GPS mapped record will be maintained of parks for reference," said the authority.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 24 मई 2025 ---------------DATED---------------------

फ्लैट्स बिके, पर नहीं हो रहा पार्किंग अलॉटमेंट

AI Image

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : द्वारका सेक्टर-14 में डीडीए के द्वारका ग्रीन्स प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए दो साल हो चुके हैं। इसके बावजूद अब तक लोगों को पार्किंग का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ऐसे में यहां रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं।

करीब दो साल पहले ई-ऑक्शन के जरिए लोगों ने ऊंची कीमत चुकाकर इन फ्लैट्स को खरीदा था। इसके बावजूद पार्किंग की अलॉटमेंट न होने से लोगों को अपनी गाड़ियां इंटरनल सड़कों पर पार्क करनी पड़ रही है। यहां रहने वाले लोगों के अनुसार यहां पर लोगों ने फ्लैट्स एक से दो करोड़ में खरीदे हैं। इतनी ऊंची कीमत लोगों ने इसलिए चुकाई क्योंकि फ्लैट्स के साथ कवर्ड पार्किंग भी दी जानी थी। बीते दो साल में लोगों ने इस पर डीडीए से कई बार बात की, लेकिन मामला अब तक सुलझा नहीं है। रेजिडेंट राजीव गुप्ता ने बताया कि बात करने पर हर बार डीडीए एक महीने में पार्किंग अलॉट की बात करता है। लोगों के अनुसार सोसायटी में 500 से अधिक परिवार रह रहे हैं और पार्किंग न होने की वजह से लोगों को काफी समस्याएं आ रही हैं। लोगों के अनुसार पैसा देने के बावजूद पार्किंग नहीं मिल रही है।

> यहां रह रहे लोगों के अनुसार यहां पर लोगों ने फ्लैट्स एक से दो करोड़ में खरीदे हैं

रामलीला कमिटियों ने फ्री बिजली, मैदान की मांग की

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

रामलीला महासंघ और अधिकारियों के बीच काफी देर तक हुई चर्चा

रामलीलाओं के सुगम आयोजन के मकसद से शुक्रवार को रामलीला महासंघ की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद प्रवीण खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में दिल्ली सरकार, नगर निगम, डीडीए, दिल्ली पुलिस, जल बोर्ड और बिजली विभाग समेत करीब डेढ़ दर्जन विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

लगभग 200 रामलीला आयोजन समितियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से आयोजन में सहयोग की मांग की।सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि रामलीला हमारे धर्म और संस्कृति की विरासत का प्रतीक है, इसलिए जरूरी है कि इस उत्सव को हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाए और इसके आयोजन में बाधा बनने वाली जटिलताओं को समय रहते दूर किया जाए। उन्होंने एक सरल एसओपी बनाने की वकालत की। बैठक में कथावाचक संत अजय भाई ने इस बार राम जन्म के साथ-साथ सीता जन्म के मंचन का आग्रह किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

बैठक में बताया गया कि दिल्ली में छोटी-बड़ी मिलाकर 500 से अधिक रामलीलाओं का आयोजन होता है। अधिकांश बड़ी लीलाएं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में होती है। इस बार रामलीलाओं का आयोजन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा और 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा।

रामलीला आयोजन कमिटियों की ओर से मांग रखी गई कि डीडीए और एमसीडी आयोजन स्थलों के मैदान 45 दिन पहले उपलब्ध कराएं और इसके लिए कोई शुल्क न लिया जाए। बिजली घरेलू दर पर या निशुल्क दी जाए, न कि कमर्शल रेट पर। जल बोर्ड भी निशुल्क पेयजल उपलब्ध कराए। एनओसी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए और पुलिस आयोजन के लाइसेंस के लिए समय रहते सूचना जारी करे। सरकारी विभागों के साथ समन्वय के लिए 11 सदस्यीय कमिटी भी बनाई गई है, जिसका नेतृत्व अर्जुन कुमार करेंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
NAME OF NEWSPAPERS-- नई दिल्ली, 24 मई, 2025 ----------------DATED--------------------

अतिक्रमण हटाने के लिए एनडीएमसी को दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: जिला प्रशासन ने नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) सहित विभिन्न विभागों के लिए अतिक्रमण, जलापूर्ति, नाले सफाई, भूमि आवंटन और अवैध पार्किंग जैसे मुद्दों पर ठोस कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने एनडीएमसी को आरके पुरम और महिपालपुर क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और अगली बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

एनडीएमसी को जलापूर्ति की समस्या का समाधान करने और तिलक लेन के पास से कचरा हटाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, पार्कों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी एनडीएमसी को सौंपी गई है। मुनिरका सब-स्टेशन के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने हेतु डीडीए को बीएसईएस के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियों को प्राथमिकता के आधार पर नाले साफ करने और अतिक्रमण तथा अवैध पार्किंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पांडव नगर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के नीचे ड्रेन निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं के समाधान हेतु एमसीडी को रेलवे से समन्वय करने का आदेश दिया गया है।

मसूदपुर एसटीपी से संबंधित मामले में डीडीए को पंपिंग स्टेशन का लेआउट और नक्शा शीघ्र डीजेबी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग को डीजीएचएस के साथ मिलकर लंबित यूडीआईडी कार्ड मामलों की मासिक समीक्षा करने का आदेश दिया गया है।

अब बिना चार्ज दिए डीएलएफ छतरपुर फार्म के रास्तों का उपयोग कर सकेंगे आम लोग

विनीत त्रिपाठी • जागरण

नई दिल्ली : छतरपुर फार्म वेलफेयर सोसायटी द्वारा वर्षों से गेट लगाकर आम नागरिकों को रास्ते का उपयोग करने से रोकने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थानीय लोगों के पक्ष में अहम निर्णय सुनाया है। छतरपुर एक्सटेंशन के निवासियों की याचिका पर न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने निर्णय दिया कि डीएलएफ छतरपुर फार्म के रास्तों से आम नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी जाए और इसके लिए कोई चार्ज नहीं वसूला जाए।

अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव को डीएलएफ छतरपुर फार्म की स्थिति का आकलन करने का भी निर्देश दिया। साथ ही पूछा कि क्या डीडीए अधिनियम 1957 लागू होने के बाद कोई निजी सड़क हो सकती है? मुख्य सचिव डीडीए, एमसीडी समेत अन्य विभागों की बैठक बुलाएं, ताकि आकलन किया जा सके कि कुछ निजी पक्षकारों द्वारा निजी सड़कों के रूप में कैसे दावा किया जा रहा है? इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 सितंबर तय कर दी और मुख्य सचिव को आकलन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

ये रास्ते थे प्रतिबंधित: याचिका में कहा गया था कि तीन सड़कों छतरपुर-भाटी रोड, छतरपुर-मांडी रोड और छतरपुर-सुल्तानपुर रोड पर गेट लगाकर गैरकानूनी तरीके से आम नागरिकों के रास्ते को प्रतिबंधित किया गया है।

छतरपुर फार्म वेलफेयर सोसाइटी का गेट नंबर-1 • सौजन्य : स्थानीय निवासी

वसूलते हैं ₹2,950 सालाना

छतरपुर से सुल्तानपुर जाने के इस रास्ते पर सोसायटी ने बाउंसर तैनात कर रखे हैं। यह भी दावा किया गया है कि इन रास्तों के इस्तेमाल के लिए पांच साल से आम लोगों से चार्ज वसूला जा रहा है। वर्तमान में स्थानीय नागरिकों को रास्ते के उपयोग के लिए 2,950 रुपये का सालाना कूपन लेना पड़ता है।

हिन्दुस्तान नई दिल्ली, शनिवार, 24 मई 2025

फ्लैट आवंटन के सवा साल बाद भी पार्किंग नहीं मिली

परेशानी

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। फ्लैट आवंटित होने के सवा साल बाद भी द्वारका सेक्टर-14 के ग्रीन अपार्टमेंट के निवासियों को पार्किंग अलॉट करने के लिए ड्रॉ का इंतजार है।

डीडीए ने 23 नवंबर 2023 को नई आवासीय योजना फ्लैट खरीदारों के लिए निकाली थी। इसके तहत द्वारका सेक्टर-14 में 316 एलआईजी फ्लैट को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुकिंग शुरू की थी। इसके अतिरिक्त 316 एमआईजी फ्लैट की ई-नीलामी शुरू की थी। द्वारका सेक्टर-14 के अपार्टमेंट में फरवरी 2024 तक अधिकतम खरीदारों को फ्लैट आवंटित हो गए थे। फ्लैट खरीदारों के अनुसार अपार्टमेंट में प्रति फ्लैट एक वाहन के पार्किंग अलॉट करने के लिए ड्रॉ निकाला जाना था। लोगों ने एलआईजी फ्लैट को 85 से 95 लाख रुपये में खरीदा था। एमआईजी फ्लैटों को ई-नीलामी के तहत एक करोड़ 25 लाख रुपये से दो करोड़ चार लाख रुपये तक खरीदा था। कई बार शिकायत के बाद भी पार्किंग आवंटित करने के लिए ड्रॉ प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। इस संबंध में डीडीए के अधिकारियों ने कहा कि पार्किंग अलॉट करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे।

डीडीए फ्लैट के लिए 27 मई से शुरू होगी बुकिंग

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपना घर आवास योजना के तहत 7500 फ्लैट निकाले हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट खरीदने का अवसर मिलेगा। बुकिंग डीडीए की वेबसाइट पर 27 मई दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है। लोकनायकपुरम, सिरसपुर और नरेला में फ्लैट खरीदने का अवसर मिलेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MAY 25, 2025 DATED---------------------

Arogya Mandir plan's implementation may not be easy in capital

Anuja.Jaiswal@timesofindia.com

New Delhi: A review of 429 sites identified for Ayushman Arogya Mandir (AAM) subcentres under the PM-AB-HIM scheme revealed significant challenges in implementation at some of the sites. Of these Municipal Corporation of Delhi (MCD) locations, 100 fall outside MCD jurisdiction, 61 remain unidentified, with the rest distributed across various MCD departments.

These issues came to light during a review meeting held on May 22, chaired by Delhi's Health and Family Welfare secretary. The meeting focused on evaluating the status of building upgrades across land-owning agencies slated for AAM development. MCD officials were directed to submit no-objection certificates (NOCs) and provisional estimates for sites under MCD (health) by May 31, 2025.

The initial plan designated 910 locations across govt bodies and PSUs for AAM establishments. This included 429 MCD sites, 91 Delhi govt locations, 109 DDA sites, 39 DJB locations, 56 DOE sites, 95 DUSIB locations, 42 Gram Sabha sites, 10 NDMC locations, 7 BVK sites, and 32 from other organisations.

DJB officials reported that several of their 39 allotted sites were located within water treatment facilities, rendering them unsuitable for health centres. NDMC confirmed that site inspections are ongoing, while DDA officials noted that site assessments are still underway. DDA requested detailed AAM establishment guidelines and committed to submitting feasibility reports by May 26.

DUSIB representatives stated that NOCs had been provided for seven sites. However, new authorisations specifically for AAMs were needed, as earlier NOCs had been issued under the now-repurposed mohalla clinic framework.

Meanwhile, officials from MCD and NDMC received instructions to complete the construction of 33 AAM by May 29, prior to the formal inauguration set for May 31, which marks the conclusion of the govt's 100-day agenda. The distribution of these 33 centres includes 20 facilities being established in Public Works Department (PWD) structures, including one at the Delhi Secretariat. Additionally, 11 centres will operate from MCD locations, while two will be situated in NDMC buildings.

Health minister Pankaj Kumar Singh announced that the govt aims to establish at least 200 AAMs in the next two months. Each AAM will provide 12 comprehensive service packages, including maternal and child healthcare, vaccinations, and more. Officials said the goal is to set up around 15 AAMs in every assembly constituency to ensure community healthcare for all.

GAPS IN AAM SITE IMPLEMENTATION

429 MCD sites for establishing AAMs

100 outside MCD jurisdiction

61 remain unidentified

Target: 33 sites across 11 districts by May 31

PWD 20 Sites
Includes | Geeta Colony, Bawana, Shalimar Bagh, Karkardooma, Chhatarpur

MCD 11 Sites
Includes | Yamuna Vihar, Babarpur, Defence Colony, Tughlakabad, Moti Nagar

NDMC – 2 Sites Sarojini Nagar, Babarpur

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- Hindustan Times NEW DELHI SUNDAY MAY 25, 2025

DDA plans to irrigate parks across Capital with treated wastewater

Snehil Sinha
snehil.sinha@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) plans to develop a citywide network for supplying treated water to parks and green belts in a bid to adopt sustainable practices by increasing water utilisation , officials aware of the matter said.

DDA is inviting proposals from consultants to design the network that uses treated wastewater instead of groundwater to irrigate nearly 750 parks under its jurisdiction. DDA owns and maintains most of the parks, green belts and Yamuna floodplains across the city.

The plan seeks ideas and expertise for a "comprehensive management strategy and technical blueprint' to deliver recycled water to parks across the National Capital Territory".

"DDA wants applicants to submit innovative, environmentally sustainable and cost-effective ideas. The scope includes mapping water demand in regions and identifying nearby sources of treated wastewater," said an official. The project will be implemented across the 10 horticulture divisions of DDA.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE SUNDAY EXPRESS, MAY 25, 2025

HC raps Delhi govt for failing to open new school in Kirari

'Authorities concerned lack necessary resolve'

SOPHIYA MATHEW
NEW DELHI, MAY 24

THE DELHI High Court has rapped the Delhi government and its agencies for failing to open a newly constructed government school in Northwest Delhi's Kirari despite the building being ready and staff already appointed.

The court has directed that all deficiencies be fixed and the school be made functional by July 15 without fail. It observed: "It appears the authorities concerned lack the necessary resolve to start the functioning of the school... the infrastructure which has been created is yet to be utilised. Such an approach cannot be appreciated for the reason that despite public money having been spent by the government, the school is not running as no admissions could be made."

This direction comes six years after a local NGO filed a petition pointing to the complete absence of a government school within a 3-4 km radius in the area.

The Indian Express on May 16 reported that two government schools, including the Kirari school, have been lying unused for months despite being inaugurated. The Kirari school was inaugurated by the previous AAP government this January.

The court, in its May 21 order, uploaded on Saturday, noted not just the delay in construction and approval processes, but lack of coordination among government departments in ensuring the school becomes operational.

The case was filed in 2019 by Hamara Prayas Samajik Utthan, an NGO working on education rights. The HC had disposed of the matter back then after directing the Delhi Development Authority (DDA) to allot land for the school. The land was eventually granted, and the building at Prem Nagar 3 in Kirari was constructed and inaugurated in January 2025.

The Indian Express report dated May 16

But over a year later, the school remains closed.

On May 21 this year, a division bench of Chief Justice D K Upadhyaya and Justice Tushar Rao Gedela took up the matter again after the petitioner NGO filed a fresh application seeking directions to make the school functional.

The court reviewed inspection reports from two meetings held in April and May this year. The reports detailed several serious problems in the school building:

- There is no electricity, as the budget for the connection has not yet been approved.
- The septic tank capacity is inadequate to handle the expected 4,000 students.
- There is no sewage connection or any alternative system for wastewater disposal.
- All science and vocational labs are incomplete, lacking plumbing and fittings.
- Building has open balconies, gaps in staircases, and unsecured rooftop gates, which the court noted could be dangerous for children.
- Furniture is insufficient, especially for the primary wing.

"Demand note of electric connection has already been generated by TPDDL, but the budget has not been allotted to the electricity department of the PWD by the Directorate of Education, GNCT of Delhi. The issue has been pursued with the higher authorities for further action," informed the PWD.

There is no access road to the school, making it physically difficult for students and staff to reach. In this regard, officials during meetings instructed the school head to give a reminder to the DDA on construction of an approach road to the school.

All of these problems, the court noted, have been known to the government for months, but nothing has moved. "Such an approach cannot be appreciated," the bench said, "... The school, as we have been informed, is supposed to cater to 4,000 children in the vicinity, which, in itself, should have prompted the authorities to make the school functional."

The court has ordered the matter to be placed directly before the Secretary, Department of Education, who must personally ensure that all pending issues are resolved and the school starts operating by July 15.

"During this period, the deficiencies... may be made good by all departments concerned in all respects," the order said.

The court also directed the DDA to immediately start work on constructing the access road to the school and complete it at the earliest.

To ensure the school doesn't lose another academic session, the bench instructed the Education Department to begin the admission process immediately and give wide publicity, inviting students to apply. Affidavits detailing progress must be submitted by Secretary of Education and DDA V-C by the next hearing on July 23.

When contacted, PWD Minister Parvesh Sahib Singh had earlier told *The Indian Express*, "I've taken immediate note of this issue and directed the authorities concerned to ensure that all essential facilities are put in place at the earliest..."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली, रविवार, 25 मई 2025

हिन्दुस्तान

NAME OF NEWSPAPERS-- **दैनिक जागरण** नई दिल्ली, 25 मई, 2025 ----------------

नई आवासीय योजना के लिए 27 से बुकिंग शुरू

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 7500 फ्लैटों की अपना घर आवास योजना 2025 शुरू हो गई। योजना के लिए फ्लैटों की बुकिंग प्रक्रिया डीडीए की वेबसाइट पर 27 मई दोपहर 12 से शुरू हो रही है। फ्लैट खरीदार डीडीए की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

नरेला में दस हजार सीसीटीवी लगेंगे

नई दिल्ली, व.सं.। नरेला सब सिटी परियोजना के तहत डीडीए और दिल्ली पुलिस ने मिलकर सुरक्षा और कानूनी ढांचे को बेहतर करने के लिए योजना बनाई है। इसके तहत नरेला में विभिन्न स्थानों पर दस हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही 50 से अधिक पुलिस बूथ भी स्थापित होंगे।

इस संबंध में डीडीए और पुलिस के अफसरों ने कई बैठकें की हैं। एलजी की अध्यक्षता में भी लगातार नरेला सब सिटी परियोजना के विकास को लेकर सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठकें की गई हैं। डीडीए के अफसरों के अनुसार फ्लैट खरीदारों को नरेला में फ्लैट लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रेमनगर सर्वोदय स्कूल में सीवर कनेक्शन व सड़क का कार्य शुरू

हाई कोर्ट की फटकार का असर, सीवर कनेक्शन को खोदाई शुरू

- डीडीए ने मुख्य सड़क मार्ग से स्कूल तक शुरू किया रोड का निर्माण कार्य
- सीवर कनेक्शन न होने के कारण स्कूल शुरू नहीं होने के मुद्दे को जागरण ने उठाया था

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले जल्दबाजी में लोकार्पित किए गए किराड़ी क्षेत्र के प्रेमनगर स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय के अधूरे कार्यों पर अब काम आरंभ हो गया है। विद्यालय शुरू नहीं होने को लेकर तीन दिन पहले हाई कोर्ट की फटकार के बाद शिक्षा निदेशालय और अन्य विभाग सक्रिय दिखे। पीडब्ल्यूडी ने सीवर कनेक्शन और डीडीए ने मुख्य मार्ग से स्कूल को जोड़ने वाले रोड के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। स्कूल के सीवर कनेक्शन और रोड निर्माण का कार्य शुरू होने से अभिभावक खुश हैं।

शनिवार सुबह डीडीए के अधिकारी और कर्मचारी प्रेमनगर सर्वोदय कन्या विद्यालय पहुंचे और मिठाई बांटकर सूखी नहर रोड से स्कूल तक पहुंचने वाले रोड का निर्माण कार्य शुरू किया। रोड की लंबाई 70 मीटर है। डीडीए अधिकारी ने बताया कि रोड का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा। इससे पहले स्कूल के सीवर कनेक्शन के लिए भी काम शुरू हो गया। नवनिर्मित स्कूल की सीवर लाइन गेट तक लाकर छोड़ दी थी, किसी मेनहाल से लाइन नहीं जोड़ी गई थी, अब पीडब्ल्यूडी ने लाइन जोड़ने काम शुरू किया है। स्कूल में बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन न होने के कारण स्कूल में पढ़ाई नहीं शुरू होने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने गत 21 मई को शिक्षा निदेशालय को 15 जुलाई तक सभी अधूरे कार्य पूरा कराकर स्कूल शुरू करने के निर्देश दिए थे। साथ ही हाईकोर्ट ने दाखिला प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के आदेश दिए थे। जनहित याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने की थी। बता दें कि बिजली, पानी व सीवर कनेक्शन नहीं होने के कारण स्कूल शुरू नहीं होने के मामले को दैनिक जागरण लगातार कवर कर रहा है।

प्रेमनगर विद्यालय के सीवर कनेक्शन के लिए खोदाई करते हुए श्रमिक • जागरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ नई दिल्ली, 26 मई, 2025 दैनिक जागरण D------------------------

निगम के पार्कों में दौड़ रहा मौत का 'करंट'

ज्यादातर पार्कों में पोल को छू रहे नंगे तार, हादसे के बाद भी नहीं चेत रहे विभाग

जागरण पड़ताल

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: कालकाजी थाना क्षेत्र के महर्षि दयानंद पार्क में करंट से नौ साल के बच्चे की मौत के बाद भी विभाग को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। जिस पार्क में घटना हुई, उसी में स्ट्रीट लाइट पोल का तार एक महीने से कटा हुआ है। इस खतरे वाले हिस्से की ऊंचाई ढाई फीट के करीब है। यानी कोई भी बच्चा खेलते हुए इसे छू सकता है। आरडब्ल्यूए की शिकायत के बाद भी इसे अब तक ठीक नहीं किया जा सका। आसपास के भी एमसीडी पार्कों का यही हाल है। जागरण टीम ने हादसे के मद्देनजर रविवार को आसपास के पार्कों में खंभों की स्थिति की पड़ताल की, इसमें चौंकाने वाले दृश्य नजर आए। ज्यादातर एमसीडी पार्कों में नंगे तार पोल को छू रहे हैं। वर्षा होने पर करंट पोल के साथ ही जमीन में भी उतर सकता है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

महर्षि दयानंद पार्क में कटे हुए हैं खंभे के बेस में लगे तार

कालकाजी डीडीए फ्लैट्स के एल-वन ब्लाक के महर्षि दयानंद पार्क में 24 मई की शाम करंट लगने की घटना हुई थी। छोटे से इस पार्क में एक तरफ बैडमिंटन के लिए कोर्ट बना है तो दूसरे तरफ झूले हैं। इसी के पीछे बीएसईएस का बाक्स लगा है। ढाई फीट की ही दूरी पर स्ट्रीट लाइट का खंभा है। खंभे के बेस में लगे तार कटे हुए हैं। यही हाल गेट के बगल वाले और शेड के पास वाले खंभे का भी है। सुबह-शाम बच्चे खेलते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर आरडब्ल्यूए की ओर से एमसीडी व बीएसईएस में कई बार शिकायत की गई। हद तो यह है कि हादसा हो जाने का बाद भी इसे ठीक नहीं किया गया।

कालकाजी स्थित संतोषी माता मंदिर के सामने वाले पार्क में स्ट्रीट लाइट पोल में लगे बिजली के नगे तार व पास में खेलते बच्चे •

बुद्ध वाटिका में बेतरतीब तरीके से जोड़े गए हैं कटे तार

यह पार्क भी एल-वन ब्लाक में है। इसके रखरखाव पर ध्यान ही नहीं है। झूले खराब हो गए हैं। कूड़े का अंबार लगा है। गेट के पास ही स्ट्रीट लाइट लगी है। निवासियों के अनुसार ये सही से काम भी नहीं करती। खंभे के बेस में तीन-चार कटे-फटे तार बेतरतीब तरीके से जोड़े गए है। नंगे तार का हिस्सा खुला पड़ा है और लोहे के खंभे को छू रहा है। रखरखाव सही न होने से इसमें बच्चे कम ही आते हैं।

बुद्ध वाटिका में स्ट्रीट लाइट पोल में लगे बिजली के नंगे तार •

संतोषी माता मंदिर पार्क में बेस में लगे तार में हैं कई जोड़

मंदिर के सामने बने इस पार्क के आसपास मार्केट का भी हिस्सा है। बैडमिंटन कोर्ट और बच्चों के लिए झूले आदि लगे हैं। दोपहर बाद कई किशोर बैडमिंटन खेल रहे थे। गेट से पार्क के अंदर पहुंचते ही नजर स्ट्रीट लाइट पोल पर गई। बेस में लगे तार में कई जोड़ थे, जिन्हें टेप से चिपकाया गया था, पर कई जोड़ खुले थे। पास में ही खेल रहे किशोर इससे अनजान अपनी धुन में रहे।

कालकाजी डीडीए फ्लैट एल-वन ब्लाक स्थित पार्क में स्ट्रीट लाइट पोल में चिपका बिजली का नंगा तार • सभी फोटो- विपिन शर्मा

नई आवासीय योजना के लिए कल से बुकिंग शुरू

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 7500 फ्लैटों की अपना घर आवास योजना 2025 शुरू हो गई। योजना के लिए फ्लैटों की बुकिंग प्रक्रिया डीडीए की वेबसाइट पर 27 मई दोपहर 12 से शुरू हो रही है। फ्लैट खरीदार डीडीए की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

कुतुब गॉल्फ कोर्स में नए जिम की 200 को मिलेगी मेंबरशिप

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

डीडीए के कुतुब गॉल्फ कोर्स में बने नए जिम के लिए अब मेंबरशिप की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीडीए 200 लोगों को यह मेंबरशिप देगा।

डीडीए के अनुसार इस मेंबरशिप से मेंबर कई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। वह अपने साथ अधिकतम पांच गेस्ट को लेकर भी आ सकते है। हर गेस्ट के लिए 100 रुपये का गेस्ट चार्ज होगा। इसके साथ ही जिम मेंबर्स को अन्य कैटिगरी के तहत पार्टी वेन्यू बुक करवाने की सुविधा भी मिलेगी। जिम मेंबर अन्य सुविधाओ जैसे राउंड ऑफ गॉल्फ आदि में भी पे एंड प्ले बेस पर जा सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें चार्ज देकर ड्राइविंग रेंज, 50 बॉल की बकैट आदि की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि इन सबके लिए उन्हें निर्धारित ड्रेस कोड का पालन भी करना होगा। यह मेंबरशिप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जा रही है।

डीडीए ने शुरू किया प्रोसेस, 'पहले आओ, पहले पाओ' पर मिलेगी मेंबरशिप

अपने साथ पाच गेस्ट भी ला सकते है

यह होगी फीस

एंट्री फीस (नॉन रिफंडेबल)	- 60,000
जीएसटी 18 प्रतिशत	- 10,800
कुल सालाना फीसों	- 70,800

जिम की टाइमिंग : सर्दी और गर्मी के लिए जिम की टाइमिंग अलग-अलग है। गर्मियो में एक मार्च से 30 नवंबर तक जिम की टाइमिंग सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात नौ बजे तक है। सर्दियों में 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक टाइमिंग सुबह 6:30 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे रात 8:30 बजे तक रहेंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- millenniumpost NEW DELHI | SATURDAY, 24 MAY, 2025 D----

DDA: DWARKA FOOTPATHS SET FOR REMODELLING; RS 35 CR PROJECT

NEW DELHI: The Delhi Development Authority will remodel all footpaths along Dwarka's roads, improving designs as per Indian Roads Congress norms. The Rs 35 crore project includes repairs, drainage upgrades, and height adjustments, with a six-month deadline.

CULTURAL HERITAGE, NEW INITIATIVES AND HISTORIC CONTINUITY

Capital prepares for grand Ramlila celebrations

AAISHA SABIR

NEW DELHI: In a significant step toward organising this year's Ramlila festivities with enhanced coordination and cultural depth, the Ramlila Mahasangh—Delhi's apex body of Ramlila committees—held a key planning meeting at the Constitution Club on Thursday.

The event brought together over 200 representatives from Ramlila committees across the capital, alongside senior officials from 18 departments including the Delhi government, MCD, DDA, Delhi Police and utility agencies.

Presided over by Mahasangh president Arjun Kumar and moderated by Subhash Goel, the meeting saw active participation from Chandni Chowk MP Praveen Khandelwal, who reaffirmed the cultural significance of Ramlila. "This tradition is not merely a dramatic performance, but the soul of our heritage. The life of Shri Ram teaches dignity, courage, and commitment—values Prime Minister Narendra Modi also embodies today," said Khandelwal, calling for administrative streamlining to ensure smooth organisation.

A standout proposal came from saint and storyteller Ajay Bhai Ji, who called for the establishment of a Ramayana Research Institute in Delhi. The proposal was unanimously accepted, along with his suggestion to include a dramatic enactment of Sita's birth alongside that of Ram's—adding new spiritual depth to this year's performances.

CLOSER LOOK

» The event brought together over 200 representatives from Ramlila committees, alongside senior officials from 18 depts including Delhi govt, MCD, DDA, Delhi Police

» To ensure effective execution, an 11-member coordination committee was formed under Arjun Kumar to liaise with government departments

This year's festivities, scheduled from September 22 to October 3, will include over 500 Ramlilas across the city, culminating in Dussehra on October 2. Notably, tableaux celebrating the valour of India's armed forces will also be introduced, underlining themes of patriotism alongside spirituality.

To ensure effective execution, an 11-member coordination committee was formed under Arjun Kumar to liaise with government departments. Committees urged early ground allotments from DDA and MCD—ideally 45 days in advance—and demanded free or subsidised electricity and water, regular sanitation, and an end to extortion by unauthorised fairground operators.

Calls were also made for a single-window system for NOCs, domestic electricity tariffs, and special traffic and publicity arrangements.

MP Khandelwal advocated for a simplified Standard Operating Procedure(SOP) and promised a follow-up meeting next month to monitor progress.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- Pioneer
NEW DELHI | SATURDAY | MAY 24, 2025

Ramlila this year to salute Operation Sindoor in Delhi

VAISHNAVI MISHRA ■ New Delhi

To celebrate the victory of righteousness over evil as embodied by Lord Ram, the stellar performance of the Indian armed forces against terror sponsoring Pakistan during Operation Sindoor will reverberate at 850 Ramlila venues through short films across the city during Navratras from September 22 to October 3.

As autumn arrives in Delhi and the air turns festive with the onset of Navratri, a powerful blend of devotion, patriotism, and tradition is set to unfold across the city. This year, the capital's age-old Ramlila performances—revered for their vivid retelling of the Ramayana—will open with something never seen before: a heartfelt tribute to the bravery of the Indian armed forces. Before Lord Ram takes the stage to vanquish evil in his timeless battle against Ravan, the audiences will witness another tale of courage—this one rooted in present—day India. In a decision that blends mythology with modern-day heroism, around 850 Ramlila committees across Delhi will either stage a play, a tableau or will screen a 15 to 20-minute short film titled "Sainya Shaurya: Operation Sindoor" before their nightly shows, as per their budget.

This short film or stage enactment will highlight the Indian Army's recent offensive, Operation Sindoor, launched on May 7. This daring mission targeted terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, following the horrific Pahalgam attack in April that took 26 innocent lives. The operation, which hit nine high-profile terror locations, is now being recognised not just in military records but on cultural stages steeped in centuries-old tradition.

Continued on >> P2

Ramlila this year to salute Operation Sindoor...

Continued from >> P1 At a time when Lord Ram's victory over Ravan is reenacted to celebrate the triumph of good over evil, the inclusion of Operation Sindoor offers a poignant contemporary parallel. It's a reminder that the spirit of righteousness is alive not just in scriptures, but also in the grit and determination of the nation's soldiers.

This tribute comes as part of a larger effort by the Shri Ramlila Mahasangh, the central body coordinating these events, to celebrate the festival with deeper cultural significance. Arjun Kumar, the president of the Mahasangh, said, "The decision was taken unanimously in a recent meeting that saw attendance from over 200 Ramlila organisers. Additionally the Ramlila will be performed for 12 days from September 22 to October 3, culminating in the grand Dussehra celebrations on October 2. On October 3, Bharat Milap prasang will be performed."

But this year's festivities go beyond just one tribute. A renewed spirit of pride in heritage and commitment to improving the festival's organisation was visible during a key gathering at the Constitution Club in Delhi. Present at the meeting were senior officials from 18 departments-including Delhi Police, MCD, DDA, and the Water Board-alongside Member of Parliament Praveen Khandelwal, who emphasised that Ramlila is more than a religious performance. According to him, it is a cultural legacy that reflects the very values upheld by the country's leadership and must be preserved and promoted with dignity.

Khandelwal strongly advocated for removing administrative roadblocks and proposed a Standard Operating Procedure for Ramlila committees to follow, which would simplify permissions and ensure better coordination between the organisers and government bodies. He also called for support in providing free electricity, water, sanitation, and timely ground allotments for the festival-similar to the support given to Kanwar Yatra and Hajj.

The meeting also brought forward a visionary cultural proposal: the establishment of a "Ramayana Research Institute" in Delhi. Saint and storyteller Ajay Bhai Ji, who was present at the meeting, recommended the creation of this center to carry out dedicated research on the life and philosophy of Lord Ram. He also suggested a new addition to this year's performances-the dramatisation of Goddess Sita's birth, which was met with unanimous approval. With all these developments, the Ramlila this year is not just a reenactment of mythological tales but a vibrant canvas reflecting India's living traditions, patriotism, and spiritual depth. The inclusion of military tributes and calls for cultural research mark a shift in how festivals are being reimagined-less as mere spectacles and more as meaningful platforms that honor both divine legends and national heroes.

Delhi's Ramlila has always carried the weight of history. Its roots go back to Old Delhi's Sitaram Bazaar, where even during Mughal rule, the festival found support among emperors and commoners alike. From the time Aurangzeb tried to ban it to its revival through public support and imperial permissions under Muhammad Shah Rangila, Ramlila has stood resilient, much like the characters it brings to life.

And so, as the Ramayana unfolds once more under the glowing lights and festive music, audiences in Delhi will first pause to remember the courage of those who protect the country today. This year's Ramlila is not just about ancient battles. It is about the ongoing fight for justice, sacrifice, and the unbroken spirit of righteousness-both divine and human.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--------- दैनिक भास्कर नई दिल्ली, शनिवार 24 मई, 2025 ----DATED---------------------

अतिक्रमण पर चलेगा यूपी के सिंचाई विभाग का बुलडोजर

जामिया नगर: मकानों-दुकानों पर नोटिस लगे, 15 दिन में खाली करें

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

ओखला के जामिया नगर इलाके में नालों पर किए गए अतिक्रमण पर जल्द ही उत्तर प्रदेश (यूपी) के बुलडोजर का एक्शन होगा। यूपी के सिंचाई विभाग ने शुक्रवार को पुलिस की मौजूदगी में इस इलाके में अपनी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए कई मकानों और दुकानों पर नोटिस चिपकाकर 15 दिन के अंदर इन्हें खाली करने का आदेश दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में ओखला के जामिया नगर इलाके में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए कई घरों को गिराए जाने के नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में कहा गया है, सभी को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई नियंत्रण विभाग से संबंधित ओखला, खिजरबाबा कॉलोनी में अतिक्रमण किया गया है। इस जमीन पर बने मकान और दुकानें अवैध हैं और इन्हें अगले 15 दिनों में हटा दिया जाना चाहिए। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 मई को दिए गए निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ओखला गांव में कानून के अनुसार अनधिकृत ढांचों को ध्वस्त करने के लिए कहा गया है।

तैमूर नगर में भी चला था अवैध निर्माण पर बुलडोजर

इससे पहले मई के पहले सप्ताह में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में तैमूर नगर नाले के सफाई व निर्माण में बाधा डाल रही कई झुग्गियों को भी तोड़ा गया था। यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के 28 अप्रैल के आदेश के बाद की गई थी, जिसमें डीडीए को नाले को चौड़ाकर निर्माण में बाधा न आए, इसके लिए 5 मई को तोड़फोड़ शुरू करने का निर्देश दिया गया था। तैमूर नगर निवासी कुणाल कुमार ने दावा किया था कि 100 से अधिक घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि यहां रहने वाले लोगों को 26 अप्रैल को घर खाली करने के नोटिस मिले थे। लोगों ने बताया था कि करीब 40 साल से लोग रह रहे थे। लोगों का कहना था कि इन झुग्गियों को हटाया जाना था, तो अधिकारियों को हम लोगों को इस जगह पर निर्माण नहीं करने की चेतावनी देनी चाहिए थी। अगर चेतावनी नहीं दे पाए तो तोड़-फोड़ के कार्रवाई का नोटिस देना चाहिए। उन लोगों ने बताया कि हम चार दशकों से यहां रह रहे हैं, अब हम अपने परिवार के साथ कहां जाएंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI — 24 मई, 2025 ▸ शनिवार

पेड़ों की नहीं होगी मनमानी छंटाई :एसओपी हुई जारी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली सरकार ने पेड़ों की शाखाओं की मनमानी छंटाई को रोकने के लिए सख्त जांच सुनिश्चित करने के वास्ते एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत और पर्यावरण के प्रति दायित्वों के बीच संतुलन बैठाने के इरादे से यह कदम उठाया है। अधिकारी के मुताबिक, दो मई को जारी एसओपी में बताया गया है कि पेड़ों की छंटाई कब और कैसे की जा सकती है, खासतौर पर सड़कों, पार्कों और आवासीय कॉलोनियों जैसी अधिक आवाजाही वाली जगहों पर। उन्होंने कहा कि ये दिशा-निर्देश सार्वजनिक सुरक्षा और पेड़ों का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं और इनके तहत पेड़ों की छंटाई के लिए ऑनलाइन आवेदन करना और फोटो साक्ष्य उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। अधिकारी के अनुसार दिल्ली में अगर कोई भी व्यक्ति, सरकारी एजेंसी, नागरिक निकाय, आरडब्ल्यूए या संगठन 15.7 सेंटीमीटर या उससे अधिक परिधि वाली पेड़ों की शाखाओं की छंटाई करना चाहता है, तो उसे अब ई-वन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। अधिकारी ने बताया कि अगर पेड़ों की शाखा की परिधि 15.7 सेंटीमीटर से कम है, तो

छंटाई के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि छंटाई करने वाले व्यक्ति या एजेंसी को दस्तावेजीकरण के लिए ई-वन पोर्टल छंटाई के पहले और बाद की तस्वीरें अपलोड करनी होगी। एसओपी के मुताबिक सार्वजनिक भूमि के मामले में अगर पेड़ जीवन, संपत्ति या यातायात के लिए खतरा पैदा करते हैं, तो दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) या दिल्ली छावनी बोर्ड जैसी एजेंसियां पेड़ों की शाखाओं की परिधि की परवाह किए बिना और बिना पूर्व अनुमति के सड़कों, फुटपाथ या पार्कों में पेड़ों की तत्काल छंटाई कर सकती हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह काम वरिष्ठ बागवानी अधिकारी की देखरेख में किया जाना चाहिए और पहले व बाद के फोटो साक्ष्य वृक्ष अधिकारी के समक्ष पेश किए जाने चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- नई दिल्ली । रविवार • 25 मई • 2025 राष्ट्रीय सहारा

डीडीए की अपना घर आवास योजना-25 के लिए बुकिंग 27 से

- योजना में एलआईजी 6098, एमआईजी 482, एचआईजी 226, ईडब्ल्यूएस 694 फ्लैट
- डीडीए ने आवेदकों के लिए तैयार किए सैम्पल फ्लैट

नई दिल्ली (एसएनबी)। डीडीए की अपना घर आवास योजना-25 के लिए फ्लैट बुकिग 27 मई से डीडीए की अपना घर आवास योजना-25 के लिए फ्लैट बुकिंग 27 मई से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की घोषित अपना घर आवास योजना-25 के लिए इच्छुक खरीदार मंगलवार 27 मई से फ्लैट की बुकिंग करा सकते हैं।

इस योजना में कुल 7500 फ्लैट शामिल हैं। इसमें सबसे अधिक एलआईजी श्रेणी के 6,098 फ्लैट शामिल हैं। पहले आओ-पहले पाओ के आधार कर डीडीए ने यह आवासीय योजना 20 मई को लांच की है। यह आवासीय योजना पूरी तरह ऑन लाइन है। आवेदकों को फ्लैट की निर्धारित पंजीकरण राशि के अलावा 2500 रुपए फार्म के भी देने होंगे और यह राशि भी ऑन लाइन ही जमा करानी होगी। खासबात यह है कि डीडीए ने सैम्पल फ्लैट तैयार किए हैं, खरीदारी के इच्छुक लोग मौके पर जाकर फ्लैट को देख सकते हैं।

डीडीए ने योजना लांच करने के साथ ही आवेदन पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आवेदन पत्रिका के मुताबिक डीडीए ने ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए पंजीकरण राशि 50,000, एलजीआई श्रेणी के फ्लैट के लिए एक लाख रुपए, एमआईजी श्रेणी के फ्लैट के लिए चार लाख रुपए और एचआईजी श्रेणी के फ्लैट के लिए 10 लाख रुपए रखी है। योजना में सबसे अधिक फ्लैट एलआईजी श्रेणी के कुल 6,098, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 694, एमआईजी श्रेणी के 482 और एचआईजी श्रेणी के कुल 226 फ्लैट योजना में शामिल हैं। यह आवासीय योजना 28 अगस्त तक चलेगी। डीडीए ने आवेदन पत्र लोकनायक पुरम, सिरसपुर और नरेला में स्थित एलआईजी श्रेणी के फ्लैटों पर 25 फीसद की छूट घोषित की है। जबकि नरेला स्थित ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, . एचआईजी, लोकनायक पुरम स्थित एमआईजी फ्लैट पर 15 फीसद की छूट घोषित की है।

डीडीए ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट की कीमत 11.54 लाख से 32.35 लाख के बीच निर्धारित की है। एलआईजी श्रेणी के फ्लैट की कीमत 33 लाख से लेकर 49.9 लाख रुपए के बीच है। एमआईजी श्रेणी के फ्लैट की कीमत 1.12 करोड़ से 1.14 करोड़ रुपए के बीच निर्धारित की है। जबकि एचआईजी श्रेणी के फ्लैट की कीमत 1.60 करोड़ से 1.62 करोड़ रुपए के बीच रखी है। डीडीए ने पहली चैट-बॉट सेवा शुरू की है। कोई भी व्यक्ति इस सेवा का इस्तेमाल कर डीडीए ने जानकारी ले सकता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS- NEW DELHI | MONDAY, 26 MAY, 2025 TED------------------------

Boy electrocuted in park in Kalkaji

NEW DELHI: A nine-year-old boy got electrocuted while playing in a park in southeast Delhi's Kalkaji area, police said on Sunday.

The incident took place on Saturday night. Aryaman Chaudhary was playing at a MCD park when he came in contact with an open electric switchboard, they said.

The police said they received a PCR call regarding the incident at around 9.30 pm. Upon reaching the spot, police learned that the child, a resident of DDA Flats, Kalkaji, had been playing in the park when his ball fell near a switchboard attached to an electric pole.

"When Aryaman tried to retrieve the ball, he accidentally touched the open switchboard and received a severe electric shock," the statement said. The child was immediately rushed to a nearby hospital by locals and his family, but doctors declared him brought dead. A case under sections 289 (negligent conduct with respect to machinery) and 106 (causing death by negligence) of the BNS has been registered at Kalkaji Police Station against unknown persons, it read.

An eyewitness, Jitendra Rathore said that children were playing in the park as usual when the ball rolled near a pole. "One of the boys went to get it and touched the switchboard and got stuck to it. Another child nearby also felt a minor shock but managed to move away. The first child was stuck and couldn't move," he said. He added some women rushed to help the boy.

"One of them tried to pull him away but couldn't. Another woman managed to pull him off by his t-shirt after a lot of effort. A neighbourhood doctor began CPR immediately, and his father also tried to help. He was then taken to a hospital," Rathore said. Another resident, Bharti, said that many children play in the park every evening. The boy was playing cricket with his friends when the ball went near the pole.

"He touched it and got a strong shock. A few children and a friend tried to help and also felt the shock. We tried giving CPR, but he didn't respond," she said.

She also mentioned difficulty in getting timely medical assistance, and added, "We first went to a hospital nearby, but there were delays. An ambulance was only arranged after repeated requests," Bharti said. The police said an investigation is underway to identify those responsible for the maintenance of the electric infrastructure in the park. PTI

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE
NAME OF NEWSPAPERS-
Pioneer
NEW DELHI | MONDAY | MAY 26, 2025

Nine-year-old boy electrocuted in park in Kalkaji area

PIONEER NEWS SERVICE ■ New Delhi

A nine-year-old boy got electrocuted while playing in a park in south-east Delhi's Kalkaji area, police said on Sunday. The incident took place on Saturday night. Aryaman Chaudhary was playing at a MCD park when he came in contact with an open electric switch-board, they said.

The police said they received a PCR call regarding the incident at around 9.30 pm. Upon reaching the spot, police learned that the child, a resident of DDA Flats, Kalkaji, had been playing in the park when his ball fell near a switchboard attached to an electric pole.

"When Aryaman tried to retrieve the ball, he accidentally touched the open switchboard and received a severe electric shock," the statement said.

The child was immediately rushed to a nearby hospital by locals and his family, but doctors declared him brought dead.

A case under sections 289 (negligent conduct with respect to machinery) and 106 (causing death by negligence) of the BNS has been registered at Kalkaji Police Station against unknown persons, it read.

An eyewitness, Jitendra Rathore, told to media that children were playing in the park as usual when the ball rolled near a pole. "One of the boys went to get it and touched the switchboard and got stuck to it. Another child nearby also felt a minor shock but managed to move away. The first child was stuck and couldn't move," he said. He added some women rushed to help the boy.

"One of them tried to pull him away but couldn't. Another woman managed to pull him off by his t-shirt after a lot of effort. A neighbourhood doctor began CPR immediately, and his father also tried to help. He was then taken to a hospital," Rathore said.

Another resident, Bharti, said that many children play in the park every evening. The boy was playing cricket with his friends when the ball went near the pole. "He touched it and got a strong shock. A few children and a friend tried to help and also felt the shock. We tried giving CPR, but he didn't respond," she said.

She also mentioned difficulty in getting timely medical assistance, and added, "We first went to a hospital nearby, but there were delays. An ambulance was only arranged after repeated requests," Bharti said. The police said an investigation is underway to identify those responsible for the maintenance of the electric infrastructure in the park.

No immediate response was received from the Municipal Corporation of Delhi.